सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY •YEAR-1 • 15 MAY TO 21 MAY 2020 • VOLUME-36 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

STUDY, WORK & SETTLE IN ABROAD

No Filing Charges &
*Pay money after the visa

IELTS | STUDY ABROAD

CANADA AUSTRALIA USA

U.K SINGAPORE EUROPE

E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663

*T&C apply

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. • HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.

न्यूज

सेना ने बनाई शीर्ष दस आतंकियों की लिस्ट

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय सुरक्षा बलों ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सक्रिय शीर्ष 10 सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों की अगली लहर को बेअसर करने के लिए नए अभियान शुरू किए हैं। सुरक्षा प्रतिष्ठान के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक, ये आतंकी पाक स्थित आतंकी संगठन लश्कर, जैश, और हिजबुल से जुड़े हैं। फिलहाल सुरक्षाबलों का उद्देश्य सभी सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क को नेस्तनाबूद करना और उन्हें नाकाम करने के लिए जवाबी हमले शुरू करना है। इन शीर्ष 10 आतंकियों को पाक की खुफिया इकाई आईएसआई की मदद से संचालित आतंकी शिविरों में प्रशिक्षित किया गया था। कश्मीरी युवाओं को भर्ती करने और आतंकी हमले करने के लिए भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने से पहले वे हथियारों से अच्छी तरह से लैस थे।

10वीं, 12वीं की परीक्षा के नतीजे जल्द: निशंक

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल ने कहा है कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जारी है और 50 दिन के भीतर यह काम पूरा हो जाएगा तथा जल्दी ही परीक्षा के नतीजे आ जाएंगे। डॉ निशंक ने देशभर के शिक्षकों के साथ वीस के जरिए संवाद करते हुए यह जानकारी दी। गौरतलब है कि डॉ निशंक इससे पहले छात्रों और अभिभावकों के साथ इस तरह संवाद कर चुके हैं। डॉ निशंक ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि उत्तर दिल्ली को छोड़कर देश भर में दसवीं बोर्ड की सभी परीक्षएँ हो चुकी हैं और परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य जारी है। वहीं उन्होंने कहा, सीबीएसई की नौवी और 11वीं के छात्रों को फेल होने पर एक और मोका मिलेगा।

उद्धव ठाकरे समेत नौ लोग निर्विरोध चुने गए

मुम्बई, (एजेंसी)। सीएम उद्धव ठाकरे और आठ अन्य लोग राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। इसी के साथ सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर छाया संवैधानिक संकट टल गया। वहीं महाराष्ट्र की नौ विधान परिषद सीटों के लिए 14 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच में निर्दलीय उम्मीदवार शहबाज राठौर का नामांकन रद्द हो गया था। इसके अलावा चार उम्मीदवारों ने मंगलवार को ही अपने नाम वापस ले लिए थे। इस तरह नौ सीटों के लिए सिर्फ नौ प्रत्याशी ही बचे थे। जिसके चलते सभी निर्विरोध चुने गए। एनसीपी ने दो सीटों के लिए चार उम्मीदवारों से नामांकन दाखिल कराए थे। एनसीपी से अतिरिक्त नामांकन भरने वाले किरण पावस्करए शिवाजीराव गरजे ने अपना नाम वापस ले लिया था।

अंतिम यात्रा में शामिल 4200 लोगों पर केस

कानपुर, (एजेंसी)। कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में आस्था के केंद्र रहे शोभन मंदिर के महंत विरक्तानंद सरस्वती की अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले 4200 श्रद्धालुओं के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लघंल का मामला दर्ज किया गया है। महंत विरक्तानंद का बुधवार को कानपुर देहात के शिवली स्थित आश्रम में निधन हो गया था। उनके ब्रह्मलीन होने की खबर मिलते ही कानपुर नगर और कानपुर देहात के आसपास क्षेत्र के लोग पार्थिव देह के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने लगे थे। दूसरी ओर सुनौड़ा और जादेपुर आश्रम में भारी भीड़ जुटी थी और देखते ही देखते हजारों की तादाद लोग इकट्ठे हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद भी पुलिस सोशल डिस्टोसिंग का पालन नहीं करवा पा रही थी। कई थानों को फोर्स मौके पर पहुंची तब कहीं जाकर भीड़ पुलिस रोक पाई।

कोरोना लॉकडाउनः रेहड़ी, पटरी और ठेले पर सामान बेचने वालों के लिए 5000 करोड़

करोड़ों प्रवासी मजदूरों को अगले दो महीनों तक मुफ्त अनाज

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के दूसरे चरण की घोषणाएं कर रही हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक, गुरुवार को प्रवासी मजदूरों, छोटे किसानों, रेहड़ी वाले के लिए कई बड़े ऐलान किए गए।

भारत	कुल मामले	मौत	स्वस्थ हुए
	81,987	2,649	27,956
मध्यप्रदेश	4,426	237	2,171

नई दिल्ली, (एजेंसी)। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन के चलते संकट का सामना कर रहे प्रवासी मजदूरों को खाना और भोजन मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का इस्तेमाल करने की छूट दी है। इस फंड में केंद्र सरकार ने 11002 करोड़ रुपए दिए हैं।

वित्त मंत्री ने की राहत पैकेज की दूसरी किस्त जारी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहत पैकेज की दूसरी किस्त जारी करते हुए यह जानकारी दी। इसके साथ ही शहरी बेघरों को केंद्र सरकार के खर्च पर प्रतिदिन खाना दिया जाएगा। वहीं, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए तीन बार का भोजन शेल्टर होम्स में लोगों को उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने बताया कि 12000 स्वयं सहायता समूहों ने 3 करोड़ मास्क और 1,20,000 लीटर सैनिटाइजर का उत्पादन किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि लेबर कोड के जरिए सभी कर्मचारियों को सरकार न्यूनतम वेतन दिलाएगी।

खास बातें

1. 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले दो महीनों के लिए बिना राशन कार्ड मुफ्त अनाज की आपूर्ति होगी।
2. जो लोग गैर-कार्ड धारक हैं, उन्हें प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं और चावल के साथ एक किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा। इसपर आनेवाले 3500 करोड़ का पूरा खर्च केंद्र सरकार देगी।
3. 'वन नेशन वन राशन कार्ड' सभी प्रवासी मजदूरों के लिए लाने वाले हैं। इसकी मदद से राज्य के किसी भी उचित मुल्य की दुकान से राशन खरीद सकते हैं।
4. 23 राज्यों में 67करोड़ लाभार्थी 83 फीसदी पीडीएस की जनसंख्या अब तक इसमें कवर हो चुकी है मार्च 2021 तक हम इसे 100 फीसदी कवर कर लेंगे।
5. रेहड़ी, पटरी और ठेले पर सामान बेचने वाले हमारे 50 लाख लोग हैं उनके लिए 5,000 करोड़ की विशेष सुविधा लेकर आए हैं। 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति इनको सुविधा दी जाएगी। जो डिजिटल पेमेंट करेगा उनको इनाम भी मिलेंगे। इससे आने वाले समय में उन्हें अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
6. प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के तौर पर मनरेगा के तहत 13 मई तक 14.62 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए।
7. सरकार एक समान न्यूनतम मेहनताना अधिकार होने के पक्ष में, राष्ट्रीय स्तर पर एक न्यूनतम वेतन के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त इसके अंतर को दूर किया जाएगा।
8. आदिवासियों को कैम्पा फंड से मिलेंगे 6000 करोड़।

छोटे व्यवसायियों के लिए 1500 करोड़

- छोटे कारोबारियों को मुद्रा योजना में 50 हजार के कर्ज पर ब्याज दो फीसदी की राहत देंगे,इसके लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया है।
- **किसानों के लिए:** 3 करोड़ किसानों को कृषि ऋण में अगले 3 महीने तक मिलेगी छूट। 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड सेंक्शन हुए, इनकी लोन लिमिट 25 हजार रुपए। पिछले मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख ऋण मंजूर किए गए जिसकी कुल राशि 86600 करोड़ रुपया है जिससे कृषि क्षेत्र को बल मिला है। किसानों की फसल खरीद के लिए 6700 करोड़ रुपये, नाबार्ड में सहकारी बैंक ऑफ ग्रामीण बैंकों की मदद के लिए 28,500 करोड़ रुपए मार्च 2020 में दिए।
- **2.5 करोड़ नए किसान क्रेडिट कार्ड होंगे जारी:** 2.5 करोड़ किसानों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं हैं। इन्हें भी यह सुविधा दी जाएगी और उन्हें 2 लाख करोड़ के लोन मुहैया कराए जाएंगे। यह सुविधा किसानों के अलावा पशुपालकों और मछुआरों को भी मिलेगी।
- **गरीबों के लिए:** शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ रुपए की मदद की गई है। एसडीआरएफ के जरिए मदद दी जा रही। गरीबों के लिए बने शेल्टर होम में तीन वक्त का मुफ्त खाना। जिनके पास राशन कार्ड या कोई कार्ड नहीं है, उन्हें भी 5 किलो गेहूं, चावल और एक किलो चना की मदद।
- **10 से कम वर्कर वाले संस्थानों में भी ईएसआई की सुविधा:** अब 10 से कम कर्मियों वाली कंपनियों के कर्मियों को भी ईएसआई की सुविधा मिलेगी।

वन नेशन वन राशन कार्ड क्रांतिकारी फैसला : शिवराज सिंह

भोपाल, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों, छोटे किसानों, रेहड़ी पट्टी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) आदि के लिए की गई घोषणाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए खजाना खोल दिया है। श्री चौहान ने कहा कि 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' क्रांतिकारी फैसला है, जिसके माध्यम से प्रवासी मजदूर जहां भी कार्य के लिए जाएंगे वहीं उन्हें राशन प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों को अगले दो माह तक निःशुल्क राशन तथा पांच किलो अतिरिक्त राशन प्रदाय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा रेहड़ी पट्टी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) के लिए पांच हजार करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है जो कोरोना संकट के दौर में उनके लिए बड़ी मदद साबित होगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा शिशु लोन, किशोर लोन एवं तरूण लोन के जो प्रावधान किए गए हैं, वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि 'प्रधानमंत्री आवास किफायती किराए पर मकान योजना'अत्यंत उपयोगी है। इससे शहरी प्रवासी गरीबों को अत्यंत कम किराए पर शहरों में मकान मिल पाएंगे।

पीएम मोदी ने खोल दिया है गरीबों के लिए खजाना

मजदूरों के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम: शहरी गरीबों और मजदूरों के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम की शुरुआत की जाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ये आवास तैयार किए जाएंगे। जिनमें मजदूरों को रहने की सुविधा दी जाएगी। बेहद मामूली किराये पर मजदूरों को यह सुविधा दी जाएगी। इस पर जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस स्कीम को पीएम आवास योजना के तहत लॉन्च किया जाएगा। उद्योगपति यदि अपनी ही भूमि पर बनाना चाहें तो उन्हें भी सरकार की ओर से मदद दी जाएगी।

'मुद्रा शिशु ऋण योजना': इस के तहत 50 हजार रुपए का लोन लेने वाले लोगों को ब्याज में सहायता दी जाएगी, इन लोगों को 3 माह तक ईएमआई भुगतान पर छूट दी गई थी, इसके बाद ईएमआई पर 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता अगले 12 महीने तक दी जाएगी, 3 करोड़ लाभार्थी होंगे।

घर लौट रहे 15 श्रमिकों की मौत, 67 घायल

- लॉकडाउन में अपने घर वापस जा रहे थे मजदूर
- गुना में कैंट थानांतर्गत बायपास रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा
- 54 घायल मजदूरों में से कई की हालत गंभीर

गुना/ नई दिल्ली, (आरएनएन / एजेंसी)। लॉक डाउन के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों और उनके परिजनों की विपदा पीछा नहीं छोड़ रही है और पिछले 24 घंटों में अलग-अलग राज्यों में हुए सड़क हादसों में कम से कम 15 श्रमिकों की मौत हो गई तथा 67 अन्य घायल हो गए।

गुना में मुंबई से पलायन कर उप्र के विभिन्न गांवों कस्बों में वापस लौट रहे मजदूरों से भरे कंटेनर और खाली बस की आमने-सामने की भीषण भिड़ंत में नौ मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 54 मजदूर घायल हो गए, जबकि 3 मजदूर ऐसे भी हैं जिन्हें खरोंच तक नहीं आई। घायल में कई की हालत गंभीर बताई जाती है। घटना गुरुवार तड़के 3 बजे के करीब गुना बायपास की है। रात के अंधेरे में जैसे ही दुर्घटना हुई, वीरान सड़क पर चीख पुकार से गूंज उठी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंच गए और घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया। ट्रक महाराष्ट्र से उप्र के उन्नाव जिले की तरफ जा रहा था। जबकि बस खाली थी और ग्वालियर से अहमदाबाद जा रही थी। प्रारंभिक पड़ताल में हादसे के लिए बसचालक को जिम्मेदार बताया गया है। उसकी तलाश जारी है। वहीं उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपए तथा हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों के उपचार के लिए 50- 50 हजार रु. की आर्थिक मदद प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं।

पैदल चल रहे श्रमिकों को बस ने कुचला, 6 की मौत

उप्र के मुजफ्फरनगर में सड़क पर चल रहे श्रमिकों को बस ने कुचल दिया। दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चार ने कुछ देर बाद दम तोड़ दिया। पांच मजदूर घायल हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और अन्य कामगारों को ट्रक से आगे रवाना किया।

रेलवे ने अब तक चलाई 800 श्रमिक स्पेशल ट्रेन 10 लाख प्रवासी कामगारों को पहुंचाया घर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के चलते फंसे हुए मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए इंडियन रेलवे की तरफ से देशभर में श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे ने गुरुवार को कहा कि एक मई से अब तक 800 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया है। इस दौरान 10 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाया गया है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन 25 मई से देशभर में लागू की गई थी। इनमें से सबसे अधिक ट्रेनें उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए चलाई गई हैं। रेलवे ने बताया कि 14 मई 2020 तक देशभर के विभिन्न राज्यों से कुल 800 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा चुका है।

भोपाल जिले में मिले 26 नए पॉजिटिव

भोपाल में कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 934 पहुंची

भोपाल, (आरएनएन)। भोपाल जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या सतत वृद्धि जारी है। गुरुवार को भी 26 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 934 पहुंच गई है। 26 मरीजों में एम्स के पीजी हॉस्टल में रहने वाली 26 वर्षीय डॉक्टर भी शामिल हैं, जो संक्रमित निकले हैं। उनको एम्स में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है। इनकी कॉन्ट्रेक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है। इन सभी संक्रमित व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। वहीं 29 नए कंटेंनमेंट क्षेत्र घोषित किए गए।

अब सुभाष कॉलोनी क्षेत्र बन गया रेड जोन : इधर, जहांगीराबाद, मंगलवारा के बाद अब सुभाष कॉलोनी क्षेत्र भी यह रेड जोन बन गया है। यहां बीते पांच दिनों से लगातार कोरोना संक्रमित मरीज निकल रहे हैं। इधर, तहसील

करोना आपदा में भोपाल का सबसे बड़ा हाट सेंटर बने जहांगीराबाद कंटेंट एरिया से निकलते लोग।

हुजूर के ग्राम जाटखेड़ी में भी कोरोना संक्रमण ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। इस क्षेत्र में दो नए मरीज मिले हैं। इनमें से एक ढोलक बस्ती का रहने वाला है, तो दूसरा जाटखेड़ी गांव का निवासी है। वहीं 18 लोग चिरायु अस्पताल से स्वस्थ होकर घर पहुंचे।

इंदौर में 61 पॉजिटिव, दो मौत 42 स्वस्थ हो घर लौटे

इंदौर, (आरएनएन)। गुरुवार रात को जारी कोरोना हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 1053 टेस्ट में से 61 की रिपोर्ट पॉजिटिव रही। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2299 हो गई। विभिन्न अस्पतालों से 42 मरीज डिस्चार्ज हुए। इस प्रकार इंदौर में 1098 संक्रमित स्वस्थ हो घर लौटे। रिपोर्ट के मुताबिक दो मरीजों की मौत हो गई। इस प्रकार संक्रमण से मृतकों की संख्या 98 हो गई है।

मप्र में 253 केस: मप्र में गुरुवार को 253 नए केस सामने आने के बाद अब कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 4426 हो गई है, वहीं इस बीमारी की चपेट में आने की वजह से 237 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जबकि 2171 व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर को लौट चुके हैं। 4 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 253 नए मामले सामने आने के बाद इनकी आकड़ा अब 4173 से बढ़कर 4426 हो गई।

केंद्रीय मंत्री प्रसाद का आरोप- कांग्रेस नेता ने लंदन कोर्ट में दी नीरव के पक्ष में गवाही

नई दिल्ली ■ एजेंसी

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया है कि पूर्व जज और कांग्रेस नेता ने लंदन की अदालत में भगोड़े नीरव मोदी के पक्ष में गवाही दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को बचाती रही है।

नीरव मोदी को कौन बचा रहा है...

अब जब नीरव मोदी को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसे प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाने की कोशिश हो रही है तब कांग्रेस के ये नेता उन्हें अदालत में बचा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद का इशारा इलाहाबाद हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के जज रहे अभय थिप्से पर था जो रिटायर होने के बाद 2018 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे।भाजपा के रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि अत्यधिक संदिग्ध परिस्थितियां बताती हैं कि कांग्रेस नीरव मोदी को बचाने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की लंदन की एक अदालत में सुनवाई चल रही है। इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए सुनवाई में भाग लेते हुए थिप्से ने कहा कि सीबीआई द्वारा नीरव मोदी पर लगाए गए आरोप भारतीय कानूनों के तहत नहीं टिक पाएंगे।

इधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया, यहाँ भारत में राहुल गाँधी नीरव मोदी को लेकर सरकार से सवाल पूछते है .. दूसरी तरफ राहुल के खास एवं कांग्रेसी अभय थिप्से (पूर्व जज) नीरव मोदी के पक्ष में गवाह बनते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो राहुल नहीं चाहते नीरव भारत आए? उस रात पार्टी में राहुल और नीरव में क्या लेन देन हुई थी?

दखल

बस्ते के वजन पर भी हो बात

शिक्षा प्रणाली को लेकर हमारे यहां अनगिनत प्रयोग तो हुए पर बच्चों की पीठ पर लदे किताबी वजन को लेकर कभी कोई अर्थपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया। इस बार कोरोना के चलते स्कूल-कॉलेज बंद हैं। लिहाजा सरकार के पास समय है। जब भी स्कूल खुलें, बच्चों के बस्ते के वजन को लेकर फैसला लागू कराना ही चाहिए। साथ ही बस्ते के बोझ से जुड़ी अंकों की दौड़ और हर विषय में आगे रहने की होड़ में औरों से पीछे छूट जाने का भय उन्हें अवसाद का शिकार बना रहा है।

यह समय संकट का है, यह सभी जानते हैं। कोरोना वायरस के चलते स्कूल-कॉलेज बंद हैं। स्कूलों में छात्रों की आमद कब होगी पता नहीं। कई राज्यों ने अपने यहां स्कूलों को खोलने की कोई गाइडलाइन जारी करने से बच रहे हैं। हालांकि, एक न एक दिन देश कोरोना की जंग जीतेगा और सब कुछ फिर से पटरी पर आएगा। लेकिन अभी सिर्फ स्कूल-कॉलेजों की बात करें तो सरकार अपना एक आदेश आज तक लागू नहीं कर पाई है और बहुत संभव है कि स्कूल दोबारा खुलने के बाद लागू न हो। यह आदेश बच्चों के बस्ते के वजन से जुड़ा है। हर साल बस्ते का वजन कम करने का आदेश जारी होता है, मगर अमल नहीं होता। यह इसलिए क्योंकि जब तक आदेश आता है, तब तक शिक्षा सत्र शुरू हो चुका होता है और आदेश रस्म अदायगी बन जाता है। इस बार अब तक सत्र शुरू नहीं हुआ है। लिहाजा सरकार इस दिशा में सोचे। हालांकि, सीबीएसई ने कोर्स कम करने की बात की है, लेकिन यह फैसला तात्कालिक है। अगले साल पुराना ढर्रा लौटेगा और बस्तों का वजन लादे बच्चे फिर से स्कूल जाते दिखेंगे।

देखा जाए तो बचपन और बोझ, यह दोनों शब्द एक-दूसरे के साथ अजीब ही नहीं गैर-जरूरी भी लगते हैं, लेकिन भारत में अनगिनत अपेक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले दबे बच्चे हर दिन बस्ते का भारी बोझ भी ढो रहे हैं। यह हमारी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा बेहद निराश करने वाला पहलू है कि सहजता से सीखने-समझने और शिक्षा पाने के मासूमियत वाले पड़ाव बच्चे किताबों का वजन ढो रहे हैं। इससे भी ज्यादा दुखद यह कि बच्चों की पीठ पर लदे बस्ते के वजन को कम करने के लिए कई बार दिशानिर्देश जारी किए गए पर हालात जस के तस हैं। इस कड़ी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्कुलर जारी कर दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के स्कूली बस्ते का बोझ भी कम करने के दिशानिर्देश दिए हैं। एचआरडी मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक छोटे बच्चों को गृहकार्य से भी छुट्टी मिल गई है। यानी अब पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को होमवर्क से मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि स्कूलों में विभिन्न विषयों की पढ़ाई और स्कूली बस्ते के वजन को लेकर भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार नियम जाएं। नए नियमों के अनुसार पहली से दूसरी कक्षा के छात्रों के बैग का वजन अधिकतम डेढ़ किलोग्राम, तीसरी से पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के बस्ते का वजन दो-तीन किलोग्राम, छठी से 7वीं के विद्यार्थियों के बस्ते का वजन चार किलोग्राम, 8वीं और 9वीं के छात्रों के स्कूल बैग का वजन साढ़े चार किलोग्राम एवं 10वीं के छात्र के बस्ते का वजन पांच किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बस्ते का बोझ कम करने के साथ ही मंत्रालय ने पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों को सिर्फ गणित और भाषा ही पढ़ाने को कहा है। इतना ही नहीं एचआरडी मंत्रालय ने तीसरी से पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों को राट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त गणित, भाषा और सामान्य विज्ञान जैसे विषयों को ही पढ़ाने का निर्देश दिया है।

दरअसल, यह पहली बार नहीं है जब बस्ते के बोझ तले दबते बचपन की परेशानियों को लेकर सोचा गया है। पीठ पर लदे बस्ते के वजन के चलते बच्चों में आ रही शारीरिक व्याधियों और मानसिक परेशानियों को लेकर लंबे समय से सोचा जाता रहा है। कई बार ऐसे दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से बस्ता हल्का करने की कोशिशों का असर अब तक न के बराबर ही रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी इस संबंध में लंबे समय से चिंतित है। इसीलिए बस्ते में से पाठ्यपुस्तकों को कम करने के सुझाव कई बार जारी कर चुका है। दो साल पहले ही फिर इस विषय को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के देशभर में अपने करीब 17 हजार संबद्धता प्रात स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बस्ते के बोझ से मुक्ति दिलाने की दिशा में कदम बढ़ाया था। बच्चों के भारी होते स्कूल बैग पर चिंतित केंद्रीय बोर्ड ने स्कूलों को एक नोटिफिकेशन जारी कहा था कि बस्ते के भारी वजन की वजह से बच्चे के समग्र विकास पर प्रभाव पड़ता है। रोजाना बस्ते का बोझ ढो रहे बच्चे माइल्ड मस्कुलर पेन के मरीज बन रहे हैं।

सीबीएसई व मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार बस्ते के बोझ की वजह से 10 से 12 साल के बच्चे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। इसीलिए सीबीएसई ने स्कूलों को हिदायत दी थी कि वे इस समस्या के निदान के लिए संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा दें और टाइम टेबल को इस तरह से तैयार करें कि बच्चों को रोजाना सभी किताबें स्कूल लाने की जरूरत ही न रह जाए, लेकिन देखने में आ रहा है बैग में पुस्तकों का वजन अब भी विशेषज्ञों द्वारा नियत भार से ज्यादा ही है। हमारे देश में स्कूली शिक्षा में क्षेत्र में लंबे समय से ऐसी सराहनीय पहल दरकार है जो बच्चों को व्यावहारिक रूप से इस बोझ से मुक्ति दिला सके। यूं भी शिक्षा का अर्थ केवल किताबी बोझ ढोना भर नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है लेकिन देखने में आ रहा है कि आजकल सरकारी हो या निजी, सभी स्कूलों में बच्चों को भारी-भरकम बस्ता थमा दिया जाता है। छोटे-छोटे विद्यार्थियों के कंधों पर भी वजनी बैग लदे हैं। जो उनकी सेहत और शिक्षा दोनों पर ही भारी पड़ रहा ह। निजी स्कूलों में तो यह वजन और भी ज्यादा है। मोटी फीस चुकाने वाले अभिभावक भी इसे लेकर सवाल नहीं उठाते क्योंकि उन्हें यह बच्चों की बेहतरी से जुड़ी बात लगती है। ऐसे में मासूमों का शरीर और मन इस बेवजह के वजन को ढोने को विवश है।

1990 में यशपाल समिति ने भी बच्चों के पाठ्यक्रम में बोझ की कमी की सिफारिश की थी, ढाई दशक से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी व्यावहारिक धरातल पर इसका असर नहीं दिखता। महाराष्ट्र में कुछ समय पहले मानवाधिकार आयोग भी इस मामले में दखल दे चुका है। आयोग के मुताबिक निचली कक्षाओं को बस्ता पौने दो किलो और ऊंची कक्षाओं का बस्ता साढ़े तीन किलो से ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए। आयोग ने फैसला बच्चों की पीठ दर्द और कंधे की जकड़न की समस्या से निजात दिलाने के लिए दिया था। इतना ही नहीं सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन के तहत करवाए गए ऐसोचैम के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में पांच से बारह वर्ष के आयु के 82 फीसदी बच्चे अत्यधिक भारी स्कूल बैग ढोते हैं। चिंतनीय है कि बस्ते का यह बोझ बच्चों में पढ़ाई के प्रति वितृष्णा का भाव तो ला ही रहा है, बीमारियां भी नई पीढ़ी को गिरफ्त में ले रही हैं गांवों से लेकर शहरों तक बच्चों का एक बड़ा प्रतिशत इस बोझ के चलते मानसिक तनाव व शारीरिक व्याधियों का शिकार बन रहा है। गांवों की परिस्थितियां तो भयभीत करने वाली हैं, जहां बच्चे बस्ता लादे कोसों पैदल चलते हैं। अंक तालिका में अव्वल जगह बनाने की दौड़ बनी हमारी शिक्षा व्यवस्था में सरकार, शिक्षक व अभिभावक बच्चों की समस्याओं लेकर उतनी गंभीरता से सोच ही नहीं पाए, जितना भावी नागरिकों के लिए सोचना जरूरी था। यही वजह है कि ऐसे दिशानिर्देशों के बावजूद कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका है।

विचार

लॉकडाउन में इस बार क्या नया

लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो रहा है। इस बार लॉकडाउन हॉटस्पॉट इलाकों तक ही रह सकता है। लेकिन जिस तरह से मरीजों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, वह संकट को बढ़ाने वाले हैं। छूट अपनी जगह है, मगर इसकी आड़ में मनमानी न हो।

18 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन 4.0 के संकेत मिलने लगे हैं। इस चरण में क्या होगा, क्या नहीं इसकी झलक दिखी है। अगर केंद्र सरकार के संकेत को ही पुख्ता मानें तो इस बार लॉकडाउन सिर्फ हॉटस्पॉट इलाकों तक रह सकता है। तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो रहा है। बाद की रणनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन सहित कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ चर्चा की है। बैठक के दौरान महानगरों में सैनिटाइजेशन व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सार्वजनिक परिवहन शुरू करने पर सहमति बनी। सरकार सीमित संख्या में रेल सेवा बहाल कर चुकी है और हवाई सेवा भी चालू करने की घोषणा की जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में रेल सेवा को जल्द ही सामान्य स्तर पर बहाल करने की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया गया। यह भी तय किया गया है कि बस और टैक्सी सेवा शुरू करने की भी इजाजत दी जाए।

बहरहाल, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में फिर से आत्मनिर्भर बनने और नया दम भरते हुए दुनिया के सामने ताकतवर रूप में उभरने का जो संकल्प दोहराया, उसमें आर्थिक पैकेज की बहुत जरूरत थी। जब कारोबार अपनी सामान्य गति में लौटेगा, तब लौटेगा, पर उसे फिलहाल इस काबिल बनाए रखना जरूरी है कि वह अपने पांवों पर खड़ा रह सके। यह आर्थिक पैकेज उसमें मदद करेगा। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि लॉकडाउन को अभी पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाएगा। इसका चौथा चरण भी लागू होगा। हालांकि उन्होंने अभी यह स्पष्ट नहीं किया कि इसकी अवधि कितनी लंबी होगी, पर यह संकेत जरूर दे दिया कि इसका रंग-रूप अलग होगा, यानी कुछ लचीला होगा। पिछले दिनों जिस तरह दिल्ली सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि अब हमें कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा, लॉकडाउन को लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता, उससे स्वाभाविक ही कयास लगाए जाने लगे थे कि सरकार शायद लॉकडाउन हटा ले।

दरअसल, लॉकडाउन की वजह से कारोबार को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। ऐसे में तमाम औद्योगिक संगठनों का दबाव था कि कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों की निशानदेही करते हुए इस बार पाबंदियों का दायरा सिकोड़ा जाए और कारोबारी गतिविधियों को शुरू किया जाए। कई राज्य सरकारें भी इसके पक्ष में नजर आ रही थीं। मगर जिस तरह कोरोना संक्रमितों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी दर्ज हो रही है और फिर बड़ी संख्या में श्रमिकों के घरों की ओर लौटने का सिलसिला चल पड़ा है, उससे संक्रमण के गांवों तक फैलने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में राज्य सरकारों के सामने चुनौती बढ़ गई है। इसलिए वे कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहतीं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती अपनी जगह है, पर नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व भी सरकारों पर है।

ई-सिगरेट पर पाबंदी लगाई जाए

ई-सिगरेट बैटरी संचालित यंत्र है जो तरल निकोटीन, प्रोपलीन, ग्लाइकॉल, पानी, ग्लिसरीन के मिश्रण को गर्म करके एक एअरोसोल बनाता है। मॉरीशस, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, ब्राजील, मेक्सिको, उरुग्वे, बहरीन, ईरान, सऊदी अरब और भारत के बारह राज्य में ई-सिगरेट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।

भारत में ई-सिगरेट बनाने और इसकी बिक्री पर बैन लगाने के लिए कानून बनाने की मांग फिर उठी है। इस कानून की आवश्यकता इसलिए है कि इसके अभाव में ई-सिगरेट के आयात पर प्रतिबंध लगाना पूरी तरह संभव नहीं है। यदि बगैर वैधानिक उपायों के ई-सिगरेट के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया तो यह वैश्विक व्यापार के मानदंडों के विपरीत होगा। इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम के आयात पर रोक लगाने के लिए अधिसूचना जारी करने की मांग वाणिज्य मंत्रालय से की थी। इस मांग में ई-सिगरेट के साथ फ्लेवर्ड हुक्का नामक मादक पदार्थ भी शामिल था। हालांकि इसकी रोकथाम की कवायद तभी से प्रारंभ हो गई थी जब पिछले साल अगस्त में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम के विनिर्माण, बिक्री एवं आयात रोकने के लिए एक परामर्श जारी किया था।

ऐसा करने के लिए आधार दिल्ली उच्च न्यायालय की मानव स्वास्थ्य को लेकर चिंता थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ई-सिगरेट के खतरों की रोकथाम में हो रही देरी पर गहरी चिंता व्यक्त की। नतीजतन, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी दवा नियंत्रकों को अपने अधिकार क्षेत्र में ई-सिगरेट व फ्लेवर्ड हुक्का सहित इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम के विनिर्माण, बिक्री, आयात व विज्ञापन की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया था। ई-सिगरेट मानव स्वास्थ्य के लिए इतनी हानिकारक है कि इस साल अप्रैल में भारत के 24 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों के एक हजार से अधिक डाक्टरों ने भारतीयों, विशेषकर युवाओं में इसकी लत लगने के पूर्व इस पर प्रतिबंध लगा देने की मांग की है। ई-सिगरेट एक बैटरी संचालित यंत्र है जो तरल निकोटीन, प्रोपलीन, ग्लाइकॉल, पानी, ग्लिसरीन के मिश्रण को गर्म करके एक एअरोसोल बनाता है जो असली सिगरेट का अनुभव प्रदान करने का कार्य करता है।

ई-सिगरेट की बिक्री सर्वप्रथम वर्ष 2004 में चीन के बाजारों में तंबाकू के विकल्प के रूप में प्रारंभ की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ष 2005 से ई-सिगरेट के व्यवसाय को वैश्विक व्यापार बनने की बात को स्वीकार करता है। वर्तमान में यह व्यवसाय लगभग तीन अरब डॉलर तक पहुंच गया है। जाहिर है, इसकी प्रवृत्ति धूम्रपान के आदी लोगों में तेजी से बढ़ रही है। धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में ई-सिगरेट के प्रति आकर्षण बढ़ने का कारण इसका दुष्प्रचार है। सिगरेट सेवन करने वालों के मध्य इस भ्रांति को फैलाया गया है कि ई-सिगरेट के सेवन से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता है। जबकि अब तक सिगरेट का सेवन करने वाले लोग इस बात से वाकिफ थे कि सिगरेट से कैंसर, फेफड़ों से संबंधी रोग, श्वसन तंत्र पर बुरा प्रभाव जैसी समस्याएं होती हैं। सिगरेट में पाए जाने वाले निकोटीन का प्रभाव सिगरेट पीने के चालीस मिनट बाद भी रहता है। इसलिए इस भ्रांति को फैलाया गया कि सिगरेट की तुलना में ई-सिगरेट बहुत हानिरहित है। इस भ्रांति ने ई-सिगरेट के व्यवसाय को वैश्विक रूप से समृद्ध बना दिया और दैनिक जीवन में धूम्रपान को जीवन शैली का हिस्सा बना चुके लोग स्वतः इस ओर आकर्षित होते चले गए।

ई-सिगरेट के प्रचलन में आने के बाद धूम्रपान करने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। निरंतर ई-सिगरेट का सेवन करने वालों की संख्या में वृद्धि होते देख ब्रिटेन की स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाली संस्था एक्शन ऑन स्मोकिंग एंड हेल्थ (ऐश) ने इसके कारणों को जानने के लिए सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में धूम्रपान करने वाले 12 हजार वयस्कों को शामिल किया गया। अध्ययन से पता चला कि ई-सिगरेट का सेवन वाले अधिकांश लोग धूम्रपान कम करने के लिए ई-सिगरेट का सहारा ले रहे हैं। सर्वे में पता चला कि ई-सिगरेट का सेवन करने वाले ऐसे लोगों की संख्या मात्र एक प्रतिशत है, जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया। नियमित रूप से सिगरेट का सेवन करने वाले लोगों में ई-सिगरेट का उपयोग करने वालों की संख्या वर्ष 2010 में 2.70 फीसद थी, जो 2014 में 17.70 फीसद तक पहुंच गई। जब धूम्रपान छोड़ चुके लोगों से ई-सिगरेट का उपयोग करने का कारण पूछा गया तो इकहत्तर प्रतिशत लोगों ने बताया कि वे धूम्रपान छोड़ने में ई-सिगरेट का सहारा लेना चाहते थे।

वहीं दूसरी ओर धूम्रपान करने वाले 48 प्रतिशत लोगों का कहना था कि उन्होंने तंबाकू की मात्रा को कम करने के लिए ई-सिगरेट का सहारा लिया। जबकि 37 प्रतिशत लोगों की राय यह थी कि उन्होंने पैसे बचाने के लिए ई-सिगरेट के विकल्प का चुनाव किया। भारत में बिकने वाली कुल ई-सिगरेट में से करीब 50 फीसद ई-सिगरेट की बिक्री ऑनलाइन होती है। इसकी आपूर्ति में चीन की बड़ी भूमिका है। ऑनलाइन उपलब्धता के चलते अब बच्चों से लेकर किशोरों तक इसकी पहुंच बहुत आसान हो गई है। ऑनलाइन बाजार जहां जीवनशैली को सुलभ एवं आसान बनाता हैं, वहीं ऐसे उत्पादों की बिक्री के चलते स्वास्थ्य एवं जीवन को संकट में भी ला खड़ा करता है। ई-सिगरेट के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को जानने के लिए किए गए एक अध्ययन में चौंका देने वाले सामने आए। तकरीबन 96 हजार लोगों पर किए गए शोध में यह बात सामने आई कि ई-सिगरेट के सेवन से दिल के दौरे का खतरा 56 प्रतिशत तक बढ़ जाता है, साथ ही लंबे समय तक इसका सेवन करने से खून के थक्के बनने की समस्या भी हो सकती है।

इतना ही नहीं, ई-सिगरेट की लत के शिकार लोगों में अवसाद का खतरा दुगना हो जाता है। ई-सिगरेट का अधिक असर गर्भवती महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य पर होता है। शोध अध्ययन के ये तथ्य उन भ्रांतियों से पर्दा उठाने के लिए काफी हैं जो बताते हैं कि ई-सिगरेट का सेवन हानिरहित है। कुछ समय पूर्व एम्स, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च व अन्य स्वास्थ्य संगठनों के डाक्टरों को शामिल कर ई-सिगरेट के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन को लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उक्त कमेटी ने 250 रिपोर्टों का विश्लेषण किया, जिसमें नतीजा सामने आया कि ई-सिगरेट से जहर फैल सकता है। कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि इसे बनाने में जिन सामग्रियों का इस्तेमाल होता है वे नुकसानदायक होती हैं और जहरीला प्रभाव पैदा कर सकती हैं।

जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस पर शोध किया है। शोध के मुताबिक साधारण तंबाकू के मुकाबले ई-सिगरेट में दस गुना अधिक मात्र में कैंसरकारी तत्व पाए जाते हैं। इसकी भाप में फॉर्मेल्डिहाइड व एसिटलडीहाइड जैसे कार्सिनोजेन तत्व पाए गए हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल इमारतों के निर्माण में होता है और ई-सिगरेट में इसकी मात्रा साधारण सिगरेट के मुकाबले ज्यादा पाई गई है। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस बात को स्वीकारा है कि वर्ष 2011 से 2013 के बीच ई-सिगरेट का इस्तेमाल करने वाले युवाओं की संख्या में खासी वृद्धि दर्ज हुई है। अतः आवश्यक है कि अब ई-सिगरेट पर रोक लगाई जाए।

ट्विटर

सरकार कोरोना के साथ आर्थिक गतिविधियों के बारे में सोच रही है। देश को लंबे समय तक बंद कर नहीं रखा जा सकता। लिहाजा, 18 मई के बाद जनता को राहत दी जाएगी।

नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री

देश में उद्योग गतिविधियां ठप हैं। अगर लॉकडाउन बढ़ाने के बाद भी सरकार ने राहत नहीं दी तो यह सभी के लिए आत्मघाती होगा और देश वर्षों पीछे चला जाएगा।

आनंद महिंद्रा, उद्योगपति

सत्यार्थ

विश्वामित्र की तपस्या

विश्वामित्र ने ऋषि, महर्षि एवं उसके बाद राजर्षि तक की उपाधि पा ली थी, मगर कोई उन्हें ब्रह्मर्षि का दर्जा नहीं दे रहा था। जब भी कहीं ऐसी कोई चर्चा चलती, उन्हें यही सुनने को मिलता था कि ब्रह्मर्षि तो वशिष्ठ हैं। विश्वामित्र ने और कठिन तपस्या शुरू की। कहते हैं, उनके तप के प्रभाव से दिग-दिगंत कांप उठे। पर लंबी तपस्या का भी वैसा कोई फल नहीं मिला, जैसा वे चाहते थे। आखिर, उनका धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने तपस्या छोड़ी और चल पड़े वशिष्ठ के आश्रम की ओर कि आज नहीं छोड़ूंगा उसे। उन्हें लग रहा था कि जरूर वशिष्ठ की इसमें कोई चाल है। वरना, ऐसा क्या कि उनके अलावा दूसरा कोई भी ब्रह्मर्षि न बन सके। यही सोचते हुए वे वशिष्ठ के आश्रम तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि चांदनी रात में ऋषि वशिष्ठ बैठे अपने शिष्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं। पास ही एक झाड़ी में छिपकर वे बातचीत सुनने लगे। एक शिष्य ने वशिष्ठ से पूछा, गुरुवर स्वच्छ आकाश में प्रकाश फैला रहे इस शीतल चांद को देख आपके मन में कौन से भाव आ रहे हैं। वशिष्ठ बोले- चांद की चांदनी वैसे ही पूरे संसार को प्रकाशित कर रही है, जैसे कि ऋषि विश्वामित्र का यश। विश्वामित्र यह सुन चकित रह गए। कहां तो मैं इन्हें मारने चला था और कहां ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। वे सामने आए व सीधे वशिष्ठ के चरणों पर गिर पड़े, क्षमा ऋषिवर, क्षमा। वशिष्ठ ने उन्हें उठाते हुए कहा, उठो ब्रह्मर्षि। इस बार विश्वामित्र समेत पूरी शिष्यमंडली चौंक पड़ी। उन्होंने कहा कि विश्वामित्र हर तरह से योग्य थे, बस उनका अहं और इस पद की लालसा उनके मार्ग की बाधा थी। जैसे ही वे पश्चाताप के आंसुओं के साथ झुके, दोनों बाधाएं दूर हो गईं व वह पद उन्हें मिल गया, जिसके वे अधिकारी थे।

कैलिफोर्निया के लॉस एंजिलिस शहर में बुधवार को समुद्र तटों पर करीब डेढ़ माह बाद लोगों की चहलकदमी देखने को मिली। हालांकि नए नियमों के तहत लोगों के लिए समुद्र तटों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। पानी में जाने की मनाही है।

बद्रीनाथ धाम के कपाट आज खोले जाएंगे

दस क्विंटल फूलों से सजा है मंदिर

नई दिल्ली ■ एजेंसी

बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुक्रवार सुबह 3 बजे से शुरू होगी। 4.30 बजे कृष्ण अष्टमी तिथि धनिष्ठा नक्षत्र में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे।

उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉ. हरीश गौड़ ने बताया कि गुरुवार को पांडुकेश्वर से रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी और धर्माधिकारी भुवनचंद्र उनियाल के साथ आदि गुरु शंकराचार्यजी की गद्दी, उद्धवजी, कुबेरजी की डोली, गाडू घड़ी यानी तिल के तेल का कलश बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं।

ऋषिकेश की श्री बद्रीनाथ पुष्प सेवा समिति द्वारा 10 क्विंटल से ज्यादा फूलों से मंदिर को सजाया गया है। गुरुवार सुबह रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी व धर्माधिकारी

भुवनचंद्र उनियाल पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ के लिए रवाना हुए थे। यात्रा में सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया।

इस साल लॉकडाउन की वजह से पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ यात्रा में रावल नंबूदरी, धर्माधिकारी, डिमरी पंचायत के प्रतिनिधि, सीमित संख्या में हकूकधारियों ने सोशियल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा और मास्क पहने। इस बार लाम बगड़ और हनुमान चट्टी क्षेत्र में इन देव डोलियों ने विश्राम नहीं किया और ना ही इन स्थानों पर भंडारे का आयोजन हुआ। बद्रीनाथ धाम पहुंच कर भगवान बद्रीविशाल के जन्म स्थान लीला ढूंगी में रावल नंबूदरी द्वारा पूजा-अर्चना की गई। सुबह 3 बजे से शुरू हो जाएगी कपाट खोलने की प्रक्रियाः डॉ गौड़ ने बताया शुक्रवार सुबह 3 बजे से कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

कुबेरजी, उद्धवजी गाडू घड़ा दक्षिण द्वार से मंदिर परिसर में रखा जाएगा। इसके बाद रावल, धर्माधिकारी, हकहकूकधारियों की उपस्थिति में कपाट खोलने हेतु प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक 4.30 बजे कपाट खोले दिए जाएंगे। कपाट खुलने के बाद लक्ष्मी माता को परिसर स्थित मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इस साल कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है। जोशी मठ के एसडीएम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कपाट खोलते समय लगभग 30 लोग ही उपस्थित रहेंगे।

न्यूज

हिमस्खलन की चपेट में सेना का दल, जवान लापता

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सेना के जवानों का एक दल उत्तरी सिक्किम के दुर्गम इलाके में अचानक हिस्खलन की चपेट में आ गया। दल के सभी सदस्यों को बचा लिया गया है लेकिन एक जवान लापता है। सेना ने बताया है कि उसका बर्फ हटाने और गश्त लगाने वाला एक दल आज उत्तरी सिक्किम में अचानक हिमस्खलन की चपेट में आ गया। इस दल में 17-18 जवान शामिल थे। बचाव दल ने त्वरित कार्रवाई कर सभी जवानों को सुरक्षित निकाल लिया लेकिन एक जवान अभी लापता है।

ठाणे व हैदराबाद से घर जाने निकले मजदूर भूख से बेहाल

मुजफ्फरपुर ,(एजेंसी)। रोटी पाने की आस में महाराष्ट्र और तेलंगाना से कभी ट्रक तो कभी पैदल मीलों लंबा सफर तय करने के बाद करीब 50 प्रवासी मजदूर घर पहुंचने की छटपटाहट में रेल पटरियों के सहारे आगे तो बढ़े लेकिन भूख और प्यास ने इतना किया बेहाल कि वे बिहार के मुजफ्फरपुर थाना पहुंच गए। महाराष्ट्र के ठाणे और तेलंगाना के हैदराबाद में काम करने वाले बिहार के करीब 50 प्रवासी मजदूर गुरुवार को पैदल रेल पटरी पर चल गांव की ओर बढ़ रहे थे कि रास्ते में उन पर एक पत्रकार की नजर पड़ गई और जब पत्रकार ने उनसे उनके बारे में जानने की कोशिश की तो उन लोगों ने कहा, हम भूखे हैं और पहले हम लोगों को कहीं से कुछ खाना खिलवा दीजिए। हम सब कोरोना की जांच कराने के लिए भी तैयार हैं।

चंपारण में वाहनों की टक्कर, 15 मजदूर घायल

मोतिहारी ,(एजेंसी)। बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के पिपराकोठी थाना क्षेत्र में वाटगंज गांव के निकट गुरुवार को दो वाहनों के बीच हुयी टक्कर में 15 प्रवासी मजदूर घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि मधुबनी जिले के बिसपी प्रखंड स्थित केरवारा गांव के रहने वाले 40 मजदूर हरियाणा की किसी कंपनी में काम करते थे। दो दिन पूर्व कंटेनर पर सवार सभी मजदूर हरियाणा से अपने घर मधुबनी जा रहे थे तभी वाटगंज गांव के समीप उनका वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक अन्य ट्रक से टकरा गया। इस दुर्घटना में 15 मजदूर घायल हो गए।

आज का इतिहास

- **1796** : फ्रांसीसी सैनिकों ने इटली के मिलान पर कब्जा किया।
- **1817** : समाज सुधारक देवेन्द्र नाथ टैगोर का जन्म।
- **1905** : अमेरिका के नेवादा प्रांत में लास वेगास शहर की स्थापना।
- **1907** : शहीदे आजम भगत सिंह और राजगुरु के साथ हंसते-हंसते फांसी के फंदे पर लटकने वाले सुखदेव थापर का जन्म।
- **1918** : अमेरिका में पहली हवाई डाक सेवा की शुरुआत।
- **1940** : मैक और डिक मैकडोनाल्ड नाम के दो भाइयों ने कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डीनो में मैकडोनाल्ड रेस्त्रां की शुरुआत की।
- **1958** : सोवियत संघ ने स्पूतनिक तृतीय रॉकेट प्रक्षेपित किया।

सरकार ने हेडलाइन पकड़ी जबकि पूरा पेज खाली था

गरीबों और भूखे प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ नहीं

नई दिल्ली ■ एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा के बाद बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेक्टर आधारित पैकेज के बारे में जानकारी। पहले से ही मोदी सरकार हमलावर कांग्रेस ने इस पर निराशा जाहिर की है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि सरकार ने सिर्फ हेडलाइन पकड़ी जबकि पूरा पेज खाली था। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया था और कहा कि यह पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का होगा, लेकिन जैसी कि उम्मीद थी कि सरकार ने हेडलाइन पकड़ लिया जबकि पूरा पेज खाली था। उन्होंने कहा कि मैं पहले बता दूं कि लाखों गरीब, भूखे और तबाह प्रवासी श्रमिकों के लिए वित्त मंत्री ने जो कुछ कहा उसमें कुछ भी नहीं था जो चल चुके हैं और हजारों लोग अभी भी वापस अपने गृह राज्य पहुंचने के लिए पैदल चल रहे हैं। यह उन लोगों के लिए एक क्रूर झटका है, जो हर दिन संघर्ष करते हैं। पी चिदंबरम ने कहा कि ऐसी आबादी (13 करोड़ परिवारों) जो बेहद निचले स्तर पर रहती है उनके लिए नकद हस्तांतरण के माध्यम से भी कुछ भी नहीं है, जिन्हें बर्बाद होने के लिए धकेल दिया गया है। प्रो थॉमस पिकेट्टी ने गरीबों के लिए नकद हस्तांतरण की बात कही थी। चिदंबरम ने कहा कि वित्त मंत्री ने MSMEs के लिए कुछ समर्थन उपायों का एलान किया, हालांकि मेरी नजर में यह उपाय बड़े MSMEs (लगभग 45 लाख MSMEs) के पक्ष में झुका हुआ है। मुझे लगता है कि 6.3 करोड़ MSMEs को छोड़ दिया गया। हम अधीनस्थ ऋण (20,000 करोड़ रुपए) और इक्वि टी कॉर्पस फंड (10,000 करोड़ रुपए) की पेशकश का स्वागत करते हैं, लेकिन हम नियम और शर्तों का इंतजार करेंगे।

केंद्र द्वारा उठाए कदम जमीनी स्तर तक पहुंचाने की हो कोशिश

बसपा अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार तत्काल और इमानदारी से इस बात का प्रयास करें कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उठाए गए कदम जमीनी स्तर तक पहुंचें। मायावती ने ट्वीट किया, अभूतपूर्व कोरोना लॉकडाउन के कारण देश की चरमराई स्थिति, अव्यवस्था व ध्वस्त अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र ने जो भी कदम उठाए हैं उस पर विश्वास करते हुए बसपा का यही कहना है कि इसको जमीन पर ईमानदारी से लागू करने की जी-जान से कोशिश तत्काल शुरू कर देनी चाहिए।

चीन से लगती सीमा पर हर तरह से जवाब देने को सेना तैयार

नई दिल्ली ■ एजेंसी

थलसेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने ने गुरुवार को कहा कि चीन के साथ लगती सीमा पर भारतीय सैनिक हर जवाब देने को तैयार हैं तथा अपनी स्थिति पर कायम हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास का काम चल रहा है।

सेना प्रमुख का यह बयान दोनों देशों के जवानों के बीच हिंसक झड़पों की दो अलग- अलग घटनाओं के कुछ दिन बाद आया है। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख और उत्तरी सिक्कम में हुई घटनाओं में चीनी और भारतीय सैनिकों का व्यवहार आक्रामक था और इस वजह से दोनों पक्षों के जवानों को मामूली चोटें आई। नरवाने ने कहा कि स्थानीय स्तर पर वार्ता के बाद दोनों पक्षों के बीच मामला सुलझा लिया गया है। उन्होंने कहा, यह बार-बार साफ किया गया है कि इन दोनों घटनाओं का न तो आपस में कोई संबंध था और न ही उनका किसी अन्य वैश्विक या स्थानीय गतिविधियों से कोई संबंध था। वह सैनिकों की झड़पों के बाद उत्पन्न गतिरोध के संबंध में संवाददाताओं के सवालों का जवाब दे रहे थे। जनरल नरवाने ने कहा, ऐसी घटनाओं के हल के लिए पहले से ही स्थापित तंत्र है। दोनों ओर के स्थानीय अधिकारी स्थापित प्रोटोकॉल और वुहान तथा मल्लापुरम में हुई बैठकों में बनी सहमति के रणनीतिक दिशानिर्देशों के अनुसार मुद्दों का समाधान कर लेते हैं।

उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिक हमेशा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखते हैं। उन्होंने कहा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी उत्तरी सीमाओं पर बुनियादी क्षमताओं का विकास पटरी पर है। कोविड-19 महामारी के कारण हमारे बलों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। समझा जाता है कि हिंसक झड़प के नौ दिन बाद भी पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे पर नजर रख रहे हैं। बता दें कि 5 मई की शाम दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। शनिवार को सिक्किम में भी नाकू ला पास के नजदीक दोनों देशों की ओर के करीब 150 सैनिकों के बीच भी कुछ इसी तरह की हिंसक झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ के कम से कम दस सैनिक घायल हो गए थे।

धार्मिक स्थल पर जुटे हजारों लोगों ने मनाया जश्न, 300 गिरफ्तार

येरुशलम, (एजेंसी)। उत्तर इजरायल में पुलिस ने लॉकडाउन के कारण लगाई पाबंदियों का उल्लंघन करने और एक धार्मिक स्थल पर एकत्रित होने के आरोप में मंगलवार को 300 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि माउंट मेरोन में जगह-जगह अवरोधक लगाने और लोगों के बड़े पैमाने पर एकत्रित होने पर पाबंदी के बावजूद सैकड़ों यहूदी आए और उन्होंने वहां मौजूद पुलिस अफसरों पर पथराव किया। यहूदी लोग बामोअर अवकाश के दिन माउंट मेरोन में इस धर्मस्थल पर एकत्र होते हैं और जश्न मनाते हैं। कोविड-19 के प्रकोप के कारण 20 लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पाबंदी है, लेकिन यरुशलम में कई स्थानों पर हजारों लोग एकत्र हुए और उन्होंने जश्न मनाया।

पाकिस्तान में रेल सेवा बहाल करने की तैयारी

पहले चरण में चलेंगी 28 ट्रेनें

इस्लामाबाद ■ एजेंसी

कोरोना महामारी से जूझ रहे पाकिस्तान में रेल सेवा और सार्वजनिक वाहनों को बहाल करने की तैयारी शुरू हो गई है। पहले चरण में 28 ट्रेनें चलाई जाएंगी। पाकिस्तान में इस खतरनाक वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पहले ही ढील दी जा चुकी है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार में गुरुवार को प्रकाशित खबर के अनुसार, पाकिस्तान रेलवे अपनी सेवाएं बहाल करने की तैयारी कर रहा है।

दिशा-निर्देश तैयार: प्रत्येक यात्रा के बाद ट्रेनों की साफ-सफाई होगी। सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे उपायों को लेकर दिशा-निर्देश भी तैयार कर लिए गए हैं। परिवहन संगठनों ने बताया कि बस स्टेशनों के गेट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। यात्रियों और ड्राइवरों के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। यात्रियों की थर्मल स्कैनर से जांच भी की जाएगी।

35 हजार से ज्यादा लोग पीड़ित

पाकिस्तान में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 35 हजार के पार पहुंच गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के अनुसार, बीते 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1,452 नए मामले पाए गए। इन्हें लेकर संक्रमित लोगों की तादात 35 हजार 788 हो गई है। 770 पीड़ितों की मौत भी हुई।

बलूचिस्तान के वित्त मंत्री भी संक्रमित

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के वित्त मंत्री जहूर बुलदी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उनका टेस्ट गुरुवार को पॉजिटिव पाया गया। उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। सिंध प्रांत के गवर्नर इमरान इस्माइल और नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर समेत कई नेता भी संक्रमित हो चुके हैं।

कोरोना महामारी के बीच न्यूयॉर्क में 102 बच्चों में मिला दुर्लभ सिंड्रोम

डॉक्टर्स के लिए बढ़ी मुसीबत

न्यूयॉर्क ■ एजेंसी

न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने कहा है कि स्वास्थ्य अधिकारी 102 ऐसे मामलों की जांच कर रहे हैं जिनमें दुर्लभ उत्तेजक सिंड्रोम की शिकायत की गई थी और संभवतः वे कोविड-19 से संबंधित हैं।

कुओमो ने बुधवार को कहा, इस सिंड्रोम ने न्यूयॉर्क सिटी के पांच साल के बच्चे, वेस्टचेस्टर काउंटी के सात साल के बच्चे और सफोक्क काउंटी के एक किशोर की जान ले ली। इस सिंड्रोम में लगातार बुखार, गंभीर पेट दर्द, आंखों का खून की तरह लाल होना और त्वचा पर लाल चकत्ते सहित विभिन्न लक्षण नजर आते हैं। कुओमो के मुताबिक, इस तरह के 71 प्रतिशत मामलों में मरीज को आइसीयू में भर्ती किया गया, 19 प्रतिशत इंटुबैशन और 43 प्रतिशत अस्पताल में भर्ती हैं। न्यूयॉर्क आक्रामक रूप से इन नए मामलों की जांच कर रहा है और इस राष्ट्रव्यापी प्रयासों की अगुआई कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के साथ काम कर रहा है, ताकि अन्य 49 राज्यों में स्वास्थ्य विशेषज्ञों को बीमारी की पहचान करने और प्रतिक्रिया देने में राष्ट्रीय मानदंड विकसित करने में मदद मिल सके।

धागंध्रा सब जेल से पांच कैदी फरार

सुरेंद्रनगर, (एजेंसी)। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की धागंध्रा सब जेल से पांच कैदी फरार हो गए । बुधवार सुबह बैरेक का ताला तोड़कर पांचों कैदी भाग गए। पांचों पर हत्या व चोरी के मामले दर्ज हैं। सूचना मिलने पर धागंद्रा पुलिस सहित उच्च अधिकारियों का काफिला आ पहुंचा। पुलिस ने नाकाबंदी कर तलाश शुरू की गई। कुछ दिन पूर्व दाहोद जिले की सब जेल से 15 कैदी फरार हो गए थे।। विचाराधीन कैदी धरम कांति, नानजी कांति, सवजी कांति, शंतु कांति तथा अन्य एक परप्रांतीया कैदी प्रकाश कुशवाह सुरेन्द्रनगर की सब जेल में बंद थे।

माल्या की याचिका ब्रिटिश हाईकोर्ट ने की खारिज

प्रत्यर्पण के तहत 28 दिन में भारत को सौंपा जा सकता है

लंदन ■ एजेंसी

बैंकों के साथ नौ हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और धनशोधन मामले में वांछित भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को गुरुवार उस समय तगड़ा झटका लगा जब ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने उसकी भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाली याचिका खारिज कर दी।

याचिका खारिज होने के बाद माना जा रहा है को माल्या को 28 दिन के भीतर भारत को सौंपा जा सकता है। इससे पहले माल्या ने एक बार फिर सरकार से अपना कर्ज लौटाने और मुकदमों को बंद करने की गुहार लगाई है।

विजय माल्या ने कोरोना वायरस चुनौती से देश की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज पर बधाई देते हुए ट्वीट कर एक बार फिर सरकार से उन पर कर्ज का शतप्रतिशत बकाया भुगतान की पेशकश और इसे स्वीकार करने और उनके खिलाफ सभी मामले खत्म करने की विनती की है। विजय माल्या ने कहा,कोविड-19 राहत पैकेज के लिए सरकार को बधाई,सरकार जितना चाहें उतने नए नोट छाप सकती है,किंतु मेरे जैसे छोटे योगदानकर्ता की पेशकश की लगातार निरंतर अनदेखी की जा रही है जो सरकारी बैंकों का शत प्रतिशत कर्ज वापस करने को तैयार है। कृपया बिना शर्त मुझसे पैसे लीजिए और मेरे खिलाफ सारे मामले बंद कीजिए।

भगोड़े शराब कारोबारी माल्या की विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस भी बंद हो चुकी है। माल्या भारत प्रत्यार्पण के खिलाफ लंदन उच्च न्यायालय में मुकदमा हार चुका है और अब इस आदेश के खिलाफ ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है।

अदाणी ने 30,000 मीट्रिक टन अनाज भेजा

मुंबई,(एजेंसी)। अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के एक हिस्से, अदाणी एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड ने लॉकडाउन के दौरान 30,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न भेजने की सुविधा प्रदान की। खाद्यान्न की यह मात्रा भारत के विभिन्न राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल आदि में 60 लाख से अधिक नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराने के बराबर है। उत्तर भारत स्थित उत्पादन केंद्रों से लेकर उपभोग केंद्रों तक खाद्यान्न के परिवहन के लिए कंपनी के स्वामित्व वाली और कंपनी द्वारा ही संचालित सात ट्रेनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। मध्य प्रदेश सरकार के साथ कारगर समन्वय बनाते हुए एएएलएल ने 15 अप्रैल से अपनी मप्र इकाइयों में पर्याप्त सुरक्षा और एहतियाती उपायों के साथ रबी फसल की गेहूं खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोविड-19 के प्रसार के तुरंत बाद भारत सरकार ने चलाई जा रही अन्य नियमित कल्याण योजनाओं के अलावा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) नाम से एक बड़ी कल्याणकारी योजना की शुरुआत की, जिसमें सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाभार्थियों को अगले 3 महीनों के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त में वितरित करने का निर्णय लिया गया।

केरल के एक परिवार को मिला 51.4 किग्रा का कटहल

गिनीज वर्ल्ड में शामिल होने के लिए किया अप्लाई

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। देशभर में मौजूद कोरोना संकट के बीच केरल में 51.4 केजी का कटहल एक प्रकार के खेत में मिला है। कोल्लम के एडामुक्कल गांव में एक परिवार को अपने खेत में 50 किलोग्राम से अधिक वजन के एक विशाल कटहल को खोज कर सभी को हैरान कर दिया है। इसके बाद इस परिवार ने अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से संपर्क किया है क्योंकि अबतक सबसे भारी कटहल का विश्व रिकॉर्ड 42.7 किलोग्राम दर्ज है।

एडामुक्कल के रहने वाले जॉनकुट्टी ने कहा कि कटहल का वजन 51.4 किलोग्राम से अधिक है और लंबाई में 97 सीएम है। न्यूज एजेंसी एएनआइ से बातचीत करते हुए करते हुए कहा कि मेरी जानकारी जुटाई की अबतक सबसे भारी कटहल का वजन 42.72 किलोग्राम जो पुणे में पाया गया था।

उम्मीद की किरण डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा, कोरोना को काबू करने में लग सकते हैं पांच साल

दुनिया भर में अब तक कोरोना से तीन लाख लोगों की मौतें

जिनेवा ■ एजेंसी

विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक का कहना है कि कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने में चार से पांच साल का समय लग सकता है। मगर उम्मीद है कि एक प्रभावी टीके से वायरस का अंत हो सकता है। वहीं अन्य विशेषज्ञों ने वायरस पर अंकुश लगाने की तारीखों की अपेक्षाओं को कम कर दिया है। पूरी दुनिया में अब तक वायरस की वजह से संक्रमितों की संख्या 4.3 मिलियन पर पहुंच गई है जबकि तीन लाख लोगों की मौत हो चुकी है।डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने एक कहा, मैं कहना चाहती हूं कि चार से पांच सालों के अंदर हम इसे नियंत्रित कर पाएंगे।

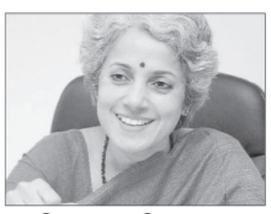

अफ्रीका महाद्वीप का प्रत्येक देश प्रभावित

कोरोना वायरस अब अफ्रीका के हर देश में पहुंच चुका है। अफ्रीका का एकमात्र देश लेसोथो अभी तक कोरोना वायरस की चपेट से दूर था मगर अब वहां भी संक्रमण का एक मामला सामने आया है।

इंग्लैंड में एंटीबॉडी टेस्ट को स्वीकृति

पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड (पीएचई) ने कोविड19 एंटीबॉडी टेस्ट किट को अपनी मंजूरी दे दी है। यह पहली बार है जब किसी एंटीबॉडी टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है। इस टेस्ट किट को स्विस कंपनी रोशे होल्डिंग एजी द्वारा तैयार किया गया है। पीएचई के विशेषज्ञों द्वारा इसके परीक्षण की सटीकता को मान्यता दी गई है।

चीन के साथ सभी संबंध खत्म कर सकता है अमेरिका: ट्रंप

वाशिंगटन, (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को चेतावनी दी कि कोरोना से निपटने के चीन के तरीकों को देखते हुए अमेरिका चीन के साथ सभी तरह के संबंधों को अस्थायी तौर पर खत्म कर सकता है। फॉक्स न्यूज के साथ इंटरव्यू में जब श्री ट्रंप से यह पूछा गया कि चीन को अमेरिका किस तरह जवाब देगा तब उन्होंने कहा कि कई चीजें हैं, जो हम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम सारे संबंधों को समाप्त कर सकते हैं। श्री ट्रंप ने यह दावा भी किया कि चीन के साथ संबंध खत्म करने से अमेरिका को 500 अरब डॉलर की बचत होगी। उनका इशारा चीन के साथ अमेरिका के व्यापार घाटे की तरफ था जो 2018 में 419 अरब डॉलर था।

ब्रिटेन में 33 हजार से ज्यादा की मौत, रूस दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश

मरने वालों की संख्या के लिहाज से ब्रिटेन दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां मरने वालों की संख्या 33 हज़ार से अधिक है मगर यहां संक्रमण के मामले रूस से कम हैं। संक्रमित लोगों की संख्या के आधार पर रूस दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है। जहां संक्रमण के 2 लाख 42 हज़ार से ज्यादा केस हैं। फ्रांस में बुधवार को कोरोना से 83 लोगों की मृत्यु हुई है, इसके बाद देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 27,074 हो चुकी है। फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार देश भर में 2,428 मरीज अभी भी इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। बीते 24 घंटे में फ्रांस में 69 नए मामले सामने आए हैं। फ्रांस के साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और स्पेन दुनिया के ऐसे देश हैं जहां कोरोना से 27 हजार से ज्यादा मौतें हुई हैं। बुधवार को स्पेन में 184 लोगों की मौत हुई है।

उद्योग विभाग ने प्लॉटों की ई-नीलामी के द्वारा जुटाए 40 करोड़ रूपए

चंडीगढ़/ब्यूरो

कैप्टन अमरिंदर सिंह के गतिशील नेतृत्व में एक और सफलता हासिल करते हुए पंजाब सरकार ने मौजूदा कोविड के चल रहे दौर के दौरान भी पीएसआईईसी द्वारा विकसित औद्योगिक और वाणिज्यिक प्लॉटों की ई-नीलामी के माध्यम से 40 करोड़ रूपए का राजस्व जुटाया है।

यह जानकारी आज यहां उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री सुंदर शाम अरोड़ा ने दी।

औद्योगिक संपदाओं के विकास के लिए राज्य सरकार की नोडल एजेंसी पीएसआईईसी ने पंजाब के अबोहर, अमृतसर, बटाला, बठिंडा, चनालों (कुराली), गोइंदवाल साहिब, कपूरथला, लुधियाना, मलौट, मंडी गोबिंदगढ़, मोहाली, श्री मुक्तसर साहिब, नया नंगल, नवांशहर, नाभा (न्यू), पठानकोट, टांडा और रायकोट में अपने औद्योगिक फोकल प्वाइंटों में स्थित औद्योगिक प्लॉटों और वाणिज्यिक स्थानों की ई-नीलामी की शुरूआत की थी।

मंत्री ने कहा कि इस नीलामी के दौरान लुधियाना, मोहाली, अमृतसर, अबोहर, पठानकोट, बठिंडा, चनालों और मलौट में स्थित औद्योगिक और वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए प्रगतिशील उद्यमियों और निवेशकों की ओर से उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखने को मिली।

पंजाब सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती विनी महाजन ने बताया कि इस नीलामी में विशेष रूप से मोहाली, लुधियाना और अमृतसर में स्थित पीएसआईईसी की वाणिज्यिक संपत्तियों के प्रति भारी प्रतिक्रिया देखने को मिली।

उन्होंने आगे बताया कि पीएसआईईसी जल्द ही पंजाब भर में औद्योगिक फोकल प्वॉइंटों में स्थित प्रमुख औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों की एक और नीलामी की योजना बना रहा है।

31 होम गार्डज़, 23 वॉलंटियर, 25 सिविल डिफेंस कर्मचारी कोरोना योद्धाओं के तौर पर कोमैंडेशन डिस्क्स और रोल से सम्मानित

चंडीगढ़/ब्यूरो

कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में पंजाब होम गार्डज़ (पी.एच.जी.) और सिविल डिफेंस कर्मचारियों द्वारा कोरोना योद्धाओं के तौर पर दी विलक्षण सेवाओं की सराहना करते हुए पी.एच.जी. और सिविल डिफेंस (सी.डी.) विभाग ने 31 पी.एच.जी., 23 वॉलंटियरों और 25 सी.डी. को नए स्थापित किए गए डीजी होम गार्डज़ कोमैंडेशन (तारीफ़) डिस्क और डायरैक्टर सिविल डिफेंस कोमैंडेशन रोल से सम्मानित किया जाएगा। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पी.एच.जी. और सी.डी. विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि 31 पी.एच.जीज़ में 3 ज़िला कमांडरों सोहन सिंह, कमलप्रीत सिंह, राज सिंह धालीवाल और 5 नॉन-गैज़ेटिड अधिकारियों, कंपनी कमांडरों सुखबीर सिंह और प्रकाश सिंह, पलटून कमांडर गुरसेवक सिंह, जसविन्दर सिंह और निर्मल सिंह को कोविड -19 के विरुद्ध लड़ाई में बेमिसाल भूमिका निभाने के लिए डीजी होम गार्डज़ तारीफ़ डिस्क से सम्मानित किया गया है।

इसी तरह 23 वॉलंटियर अजीत सिंह, कृष्ण कुमार, चरनजीत सिंह, सुरजीत सिंह, नछत्तर सिंह, खुशप्रीत सिंह, प्रदीप कुमार गौतम, शाम सुंदर, जसवंत सिंह, करनैल सिंह, रणजीत सिंह, गुरदीप सिंह, रेशम लाल, रणजीत सिंह, जोहन मसीह, रछपाल सिंह, मनजिन्दर सिंह, कुलदीप सिंह, जरनैल सिंह, कुलविन्दर सिंह, गुरमीत सिंह, अश्वनी कुमार और सुरिन्दर कुमार को भी कमाल की सेवाएं निभाने के बदले डीजी होम गार्डज़ तारीफ़ डिस्क से सम्मानित किया गया है।

इसके अलावा सिविल डिफेंस में कुलदीप सिंह, परमजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, जसप्रीत सिंह, गुरचरन सिंह, राज कुमार कश्यप, महिंदर पाल सैनी, भुपिन्दर सिंह, चरनजीत सिंह, परमजीत कपूर, बुद्ध सिंह ठाकुर, सुधीर सूद, दर्शन सिंह रहल, सुदर्शन कुमार खन्ना, सुरजीत सिंह, प्रीतपाल सिंह नाटी, मनजीत सिंह, हरजिन्दर सिंह, अभिषेक जोश, परमोध शर्मा, राकेश कुमार, रमेश कुमार, जसमिन्दरजीत सिंह, इंदरजीत खुराना और राजेश भनोट को रा%य में कोविड महामारी के विरुद्ध लड़ाई में बेमिसाल प्रदर्शन करने के लिए डायरैक्टर, सिविल डिफेंस प्रशंसा रोल से नवाज़ा गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा लुधियाना में छोटे / घरेलू उद्योगों को काम शुरू करने के लिए हरी झंडी

चंडीगढ़/ब्यूरो

राज्य में उद्योगों को पैरों पर खड़ा करने के लिए वांछित सुविधा मुहैया करवाने और विभिन्न औद्योगिक इकाईयों द्वारा ज़ाहिर की गई चिंताओं पर गौर करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज लुधियाना के ज़मीनी प्रयोग के मिश्रित गैर-सीमित इलाकों (मिक्स लैंड यूज वाले क्षेत्रों) में छोटे / घरेलू उद्योगों को तुरंत काम शुरू करने की इजाज़त दे दी है, जिससे बड़े उद्योगों को खोलने में सहायता मिलेगी, जो छोटे पुर्जों और अन्य सम्बन्धित साजो-सामान के लिए छोटी इकाईयों पर निर्भर होते हैं।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इन छोटी ईकाइयों जहाँ आम तौर पर कामगार वहां या आस-पास ही रहते हैं, को कोविड-19 के निर्धारित कार्य संचालन (एस.ओ.पी.) की सख़्ती से पालना और सीमित पहुँच की ज़रूरतों के आधार पर काम शुरू करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक इकाईयों द्वारा लुधियाना जिले के गैर-सीमित ज़ोन के ज़मीनी प्रयोग के मिश्रित क्षेत्रों में कोविड-19 के एस.ओ.पीज़ की पालना को यकीनी बनाने और सीमित पहुँच के साथ औद्योगिक इकाईयां चलाने की आज्ञा देने की बार-बार अपील की गई थी। उन्होंने कहा कि रा%य के उद्योग मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने भी सुझाव दिया था कि छोटे ईकाइयों को चलाने की इजाज़त दी जानी चाहिए, जिससे बड़े उद्योग भी अपना काम शुरू कर सकें।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उनको जानकारी दी गई है कि लुधियाना के मास्टर प्लान के अंतर्गत एस.ई.ई. / ई.ओ.यूज़ / इंडस्ट्रियल एस्टेट / फोकल प्वाइंट / मनोनीत औद्योगिक इलाकों के अधीन उद्योग चलाने के ताज़ा दिशा-निर्देशों के अंतर्गत दी गई मंज़ूरी के बावजूद लुधियाना के कुछ औद्योगिक इलाकों में उद्योग अपने काम शुरू नहीं कर सके थे।

ज़िक्रयोग्य है कि लुधियाना एक औद्योगिक शहर है जहाँ लगभग 95,000 सूक्ष्म, छोटे और मध्यमवर्गीय उद्योग हैं जो हुनरमंद और गैर-हुनरमंद 10 लाख से अधिक कामगारों को रोज़गार देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कामगार विभिन्न रा%यों से सम्बन्धित हैं और लम्बा समय लॉकडाउन रहने के कारण बेरोज़गार हो चुके हैं और उनको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि यह दूर्भाग्यपूर्ण है कि बन्दिशों में ढील दिए जाने के बावजूद लुधियाना के अंदर सिर्फ़ 6900 औद्योगिक ईकाइयों द्वारा औद्योगिक गतिविधियों शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि काफ़ी छोटी औद्योगिक इकाईयों की विभिन्न छोटी / घरेलू औद्योगिक इकाईयाँ जो मास्टर प्लान के अनुसार ज़मीनी प्रयोग के मिश्रित क्षेत्रों में स्थापित हैं, पर औद्योगिक ज़रूरतों के लिए निर्भरता होने के कारण इनकी तरफ से काम की शुरुआत नहीं की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी तरफ से ज़िला प्रशासन को औद्योगिक ईकाइयों को काम शुरू करने के लिए उत्साहित करने संबंधी निर्देश दिए गए हैं, जिससे इनमें काम करने वाले बड़ी संख्या में कामगारों को लाभ हो सके और टाऊन प्लानिंग विभाग की नोटिफिकेशन के अनुसार नोटीफाई मास्टर योजना और ज़मीनी प्रयोग पक्ष से मिश्रित क्षेत्रों की औद्योगिक ईकाइयों को काम करने के लिए मंज़ूरी दी हुई है। इसलिए इन उद्योगों, जो लुधियाना के मास्टर प्लान के अनुसार नियत औद्योगिक क्षेत्रों / फोकल प्वाइंटों / औद्योगिक एस्टेटों / एस.ई.ई. /ई.ओ.यू में आने वाले उद्योगों के लिए सप्लाई की कड़ी का हिस्सा होने के कारण भी मंज़ूरी देने की ज़रूरत है।

प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार सृजन पर 10,000 करोड़ खर्च

नयी दिल्ली, (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत पिछले दो महीने में 14.62 करोड़ मानव श्रम दिवस रोजगार सृजित किये गये। इस पर कुल 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वह यहां आर्थिक राहत पैकेज की दूसरी किस्तों की घोषणा कर रही थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था में नयी जान फूंकने के लिए 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा की थी। सीतारमण ने कहा कि 13 मई तक 2.33 करोड़ श्रमिकों को रोजगार दिया गया। पिछले साल मई के मुकाबले इस साल इससे जुड़ने वाले श्रमिकों की संख्या 40 से 50 प्रतिशत अधिक रही।वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार सुधारों पर काम कर रही है। इसमें पूरे देश में एक जैसी न्यूनतम मजदूरी लागू करना शामिल है जो क्षेत्रीय असमानता को दूर करेगी। इसके लिए सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक न्यूनतम पारिश्रमिक ढांचा तैयार करेगी।

मनरेगा के तहत मजदूरी 200 रुपए की गई

कोरोना के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था की। जो शहरी लोग बेघर हैं, उन्हें इसका फायदा मिला।जो अप्रवासी मजदूर अपने राज्यों में लौटे हैं, उनके लिए भी योजनाएं हैं। इस पर अब तक 10 हजार करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं।1.87 हजार ग्राम पंचायतों में काम हुआ है। जो मजदूर अपने घरों में लौटे हैं, वे वहीं रजिस्टर कर काम ले सकते हैं। मनरेगा के तहत मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दी गई है। न्यूनतम वेतन का लाभ 30% वर्कर उठा पाते हैं। समय पर उन्हें पैसा नहीं मिलता। गरीब से गरीब मजदूर को भी न्यूनतम वेतन मिले और क्षेत्रीय असामनता दूर हो इसके लिए कानून बनाया जाएगा।

आम आदमी : मिडिल इनकम ग्रुप जिनकी सालाना आय 6 लाख से 18 लाख तक है। उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम मार्च 2021 तक बढ़ाई जा रही है। इससे 2.5 लाख लोगों को फायदा होगा।

रोजगार निर्माण : आदिवासी इलाकों, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़े, इसके लिए 6000 करोड़ के कैम्पा फंड का इस्तेमाल किया जाएगा।

ट्रॉली बैग पर सोया बच्चा, रस्सी बांध खींचती रही मां कोरोना वायरस के खतरे के बीच दूसरे राज्यों से अपने घरों की ओर लौट रहे प्रवासी मजदूरों की भावुक कर देने वाली तस्वीरें सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। यह तस्वीर आगरा से सामने आई है, जहां पंजाब से उत्तर प्रदेश के महोबा जाने के लिए निकले एक जत्थे में शामिल बच्चा इतना थक गया कि वह चलते हुए ट्रॉली बैग पर ही सो गया। और उसकी मां ट्रॉली बैग को रस्सी से बांधकर खींचती रही।

रेलवे का यात्रियों को झटका

रेलवे ने 30 जून तक की बुकिंग कैंसिल की, यात्रियों को पूरा पैसा रिफंड होगा

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): रेलवे ने 30 जून तक बुक हुए ट्रेन टिकट कैंसिल कर दिए हैं। श्रमिक स्पेशल और स्पेशल ट्रेन चलती रहेंगी। इस फैसले से माना जा रहा है कि 30 जून तक ट्रेनों की सामान्य सेवा बहाल नहीं होगी। आमतौर पर ट्रेन के टिकट 120 दिन पहले तक बुक किए जा सकते हैं। ऐसे में लॉकडाउन से पहले ही कई टिकट बुक किए जा चुके थे।रेलवे ने बताया कि अगले आदेश तक मेल/एक्सप्रेस, पैसेंजर और सबर्वन सर्विसेस बंद रहेंगी। यात्रियों को पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा।

उधर, रेलवे ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग में 13 मई से सभी यात्रियों का डेस्टिनेशन एड्रेस लेना भी शुरू किया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में मदद मिल सके। रेलवे ने यह भी बताया कि अगले सात दिन के लिए स्पेशल ट्रेनों में 2.34 लाख यात्रियों ने टिकट की बुकिंग की है। इससे 45.30 करोड़ रुपए का रेवेन्यु मिला है। इधर, कोरोना के लक्षण की वजह से जिन लोगों को ट्रेनों में यात्रा करने से रोका जाएगा, उन्हें रेलवे टिकट की पूरी राशि रिफंड करेगा। रेलवे ने बुधवार को यह जानकारी दी। इस संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है। इसके मुताबिक, कंफर्म टिकट वाले यात्री में अगर स्क्रीनिंग के दौरान कोविड-19 के लक्षण नजर आते हैं। जैसे तेज बुखार, खांसी तो उसे यात्रा की अनुमति नहीं होगी। इस सूरत में उसका टिकट रद्द कर दिया जाएगा।

ग्रुप टिकट कैंसिल होने पर भी पूरा पैसा रिफंड होगा

वहीं, ग्रुप टिकट में अगर कोई एक मुसाफिर यात्रा के लिए अनफिट पाया जाता है और उस पीएनआर नंबर पर यात्रा करने वाले दूसरे लोग भी ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं तो उस सूरत में भी रेलवे टिकट का पूरा पैसा लौटाएगा।

मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें भी शुरू हो सकती हैं

एसी स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद रेलवे जल्द ही मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें भी शुरू कर सकता है। रेल मंत्रालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे बोर्ड ने बुधवार को आदेश जारी किया। इसके मुताबिक, 22 मई से स्पेशल एसी के साथ ही दूसरी ट्रेनों में भी वेटिंग लिस्ट वाले टिकट जारी किए जाएंगे।हालांकि, आरएसी वाले टिकट अभी जारी नहीं होंगे। रेलवे ने फर्स्ट एसी में 20 और स्लीपर में अधिकतम 200 तक वेटिंग तक टिकट बुक कराने की मंजूरी दी है। इसके साथ एसी चेयर कार, एग्जीक्यूटिव क्लास, सेकंड एसी और थर्ड एसी में भी वेटिंग टिकट बुक कराए जा सकेंगे। नई व्यवस्था 15 मई से बुक होने वाले टिकट पर लागू होगी।

महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बेकाबू

राज्य में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 25,922 हुई

मुंबई, (एजेंसी): महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। राज्य में बुधवार को 1,495 नए पॉजिटिव मिले। यह एक दिन में पॉजिटिव मिले मरीजों का सबसे बड़ा आकड़ा है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में राज्य में संक्रमण से 54 मौतें भी हुईं हैं। इनमें मुंबई में 40 की जान गई। राज्य में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 25,922 पहुंच गई है। वहीं संक्रमण से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 975 पर पहुंच गया है। राज्य में अब तक 5,547 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं।

जान गंवाने वालों का आंकड़ा 975 पर पहुंचा

'टोसिलिजुमैब' नाम की नई दवाई का इस्तेमाल शुरू : मुंबई में बीएमसी के हॉस्पिटल में गंभीर रूप से बीमार चल रहे कोरोना मरीजों को 'टोसिलिजुमैब' नाम की दवा का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। बीएमसी अधिकारियों ने बताया कि इससे मरीजों की स्थिति में सुधार भी देखने को मिला है। बीएमसी के मुताबिक, मुंबई के बीएमसी मेडिकल कॉलेज, सायन अस्पताल, नायर अस्पताल, केइएम और सेवन हिल्स अस्पताल में टोसिलिजुमैब इंजेक्शन का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। अब तक कुल 40 मरीजों पर इसका इस्तेमाल किया गया, जो इस वायरस से गंभीर रूप से प्रभावित थे और इनमें से 30 से ज्यादा मरीजों में उत्साहजनक परिणाम भी देखने को मिले हैं।

मंदिर ट्रस्ट के पास पड़े सोने को कब्जे में लेना चाहिये: अशोक चव्हाण : महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राष्ट्र को आर्थिक संकट से उबारने के लिए देशभर के मंदिर ट्रस्टों के पास रखे हुए सोने के भंडार को सरकार अपने कब्जे में ले। चव्हाण ने कहा कि यह सोना राष्ट्र की संपत्ति है और राष्ट्र के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार को यह भी सुझाव दिया कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो 1 या 2% ब्याज पर यह सोना मंदिर ट्रस्टों से ले सकती है। इस संदर्भ में चव्हाण ने अंतरराष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हवाला देते हुए कहा कि देश के मंदिर ट्रस्टों के पास लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थात 75 लाख करोड़ रुपए मूल्य का सोना है।

संजय राउत ने की मुंबई को अलग से आर्थिक पैकेज देने की मांग

शिवसेना के नेता संजय राउत ने कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित मुंबई के लिए विशेष पैकेज दिए जाने की मांग की है। राउत ने कहा, "कामगार शहर छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास यहां काम नहीं बचा है। देश की आर्थिक राजधानी के तौर पर मुंबई की महत्ता बनी रहनी चाहिए। केंद्र को मुंबई तथा नौकरियां पैदा करने वाले अन्य शहरों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करनी चाहिए।" उन्होंने कहा कि शिवसेना ने, मोदी की 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज संबंधी घोषणा का स्वागत किया है।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor: ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.